PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Jansatta, Delhi
Tuesday, 27th September 2011, Page: 6
Width: 8.03 cms Height: 6.19 cms, Ref: pmin.2011-09-27.50.41

दवा की कीमत

हमारे देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के मसले पर बड़े-बड़े वादे जरूर किए गए, लेकिन समूचे तंत्र को उपयोगी बनाने के लिए शायद ही कोई गंभीर पहल हुई। खासतौर पर सरकारी अस्पतालों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें चिकित्सक की सलाह के मुताबिक वहां दवा मुफ्त मिल सके। दूसरी ओर, खुले बाजार में बेलगाम तरीके से दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे वे गरीबों की पहुंच से दूर होती गई हैं। भारत में ऐसे परिवारों की बहुत बड़ी तादाद है जो किसी सदस्य के बीमार होने की हालत में दवा खरीद सकने में सक्षम नहीं हैं। लिहाजा योजना आयोग की एक विशेषज्ञ समिति ने उचित ही दवाओं की खरीद

PRESS INFORMATION BUREAU
प्रेस सूचना ब्यूरो
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Jansatta, Delhi
Tuesday, 27th September 2011, Page: 6
Width: 7.87 cms Height: 17.35 cms, Ref: pmin.2011-09-27.50.41

पर सरकारी बजट बढ़ाने की सिफारिश की है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के तहत दवाओं की खरीद पर भारत फिलहाल लगभग छह हजार करोड़ रुपए खर्च करता है, जो सकल घरेलू उत्पाद का महज 0.1 फीसद है। समिति ने इसे पांच गुना बढ़ा कर तीस हजार करोड़ रुपए करने का सुझाव दिया है।

एक आकलन के मुताबिक भारत में 1990 के दशक के मध्य में इलाज के दौरान संतोषजनक पैमाने पर दवा खरीद सकने वाले परिवारों की संख्या लगभग अस्सी फीसद थी, जबकि 2004 आते-आते यह अनुपात गिर कर पैंसठ फीसद हो गया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन वर्षों के दौरान दवाओं की कीमतों में किस तेजी से बढ़ोतरी हुई। यह वही दौर है जब सरकारों ने जनता के सामने चमकते भारत की तस्वीर पेश की और जल्द ही देश के एक आर्थिक महाशक्ति बन जाने के दावे किए। 2004 में जब यूपीए की पहली सरकार बनी तो साझा न्यूनतम कार्यक्रम में वादा किया गया था कि 2012 तक स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ा कर सकल घरेलू उत्पाद का दो से तीन फीसद कर दिया जाएगा। लेकिन आजादी के तिरसठ साल के बाद भी हालत यह है कि स्वास्थ्य के मद में सरकारी खर्च जीडीपी के एक फीसद से ऊपर नहीं पहुंच सका है। इस मामले में श्रीलंका, चीन और ब्राजील जैसे देश हमसे काफी आगे हैं, जो स्वास्थ्य के मद में तीन से चार फीसद तक खर्च करते हैं। यह बेवजह नहीं है कि मानव विकास के मामले में दुनिया भर में भारत की तस्वीर बेहद निराशाजनक है।

हाल ही में योजना आयोग से ही संबंधित एक समिति ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमन और विकास प्राधिकरण के गठन के अलावा एक ऐसा चिकित्सा तंत्र गठित करने की सलाह दी है जो सभी तरह की बीमारियों में आम लोगों की चिकित्सा सेवा तक आसान पहुंच सुनिश्चित करे। आयोग की विशेषज्ञ समिति की ताजा सिफारिश भी स्वागतयोग्य है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि दवाओं की खरीद में कई बड़े घोटाले सामने आ चुके हैं। बिना निविदा निकाले करोड़ों रुपयों की दवाओं की खरीदी की गई और इसके लिए अपनी पसंदीदा कंपनियों के साथ सौदे किए गए। घटिया दवाओं की आपूर्ति के भी कई मामले उजागर हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में दवा खरीद में बजट बढ़ाने के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि उस पर कड़ी निगरानी रखी जाए, वरना आबंटन में इजाफा नाजायज कमाई के अवसरों में ही बढ़ोतरी करेगा।